साप्ताहिक
जागत गांव हमार
पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक
RNI-MPHIN/2015/72544
चौपाल से भोपाल तक
भोपाल, सोमवार, 10-16 जून 2024, वर्ष-10, अंक-8
भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित
पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

बेतवा नदी के उद्गम स्थल झिरी बहेड़ा से सीएम यादव ने किया का शुभारंभ

नदियों को जीवनदान देने सरकार ने छेड़ा जल गंगा संवर्धन अभियान

» अभियान के अंतर्गत 3 हजार 90 करोड़ की लागत से होंगे जल संरक्षण के 990 कार्य

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में माना गया है कि पृथ्वी पर्वत नदी पेड़-पौधों में जीवंतता है और वे हमारे लिए पूज्यनीय हैं। जिस प्रकार मानव देह में धमनियों के माध्यम से रक्त का संचार होता है उसी प्रकार नदियां पृथ्वी पर जीवन का संचार करती हैं। अतः हम सबके लिए नदियों का अक्षुण्ण निरंतर प्रवाह जरूरी है। नदियों के प्रवाह को दूषित करना या उनमें अवरोध उत्पन्न करना जीवन में अवरोध उत्पन्न करने के समान है। इस दृष्टि से जल स्त्रोतों का संरक्षण मानव जीवन के लिए आवश्यक है।

मुख्यमंत्री विश्व पर्यावरण दिवस पर रायसेन जिले में झिरी बहेडा स्थित बेतवा नदी के उद्गम स्थल पर जल गंगा संवर्धन अभियान के शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने बेतवा नदी के उद्गम स्थल की पूजा-अर्चना कर तथा बरगद का पौधा रोपकर जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया। अभियान का समापन 16 जून को गंगा दशहरे के अवसर पर उज्जैन में होगा।

पंचायत स्तर पर होंगी गतिविधियां

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक संसाधन ईश्वरीय देन हैं। इनकी महत्ता को स्वीकारने और उसके संरक्षण के लिए निरंतर प्रयासरत रहने के उद्देश्य से ही प्रतिवर्ष पांच जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की परम्परा आरंभ हुई। पौधों में प्राण होते हैं इस तथ्य को सिद्ध करने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने कहा था कि भारतीय संस्कृति पौधों को जीवंत ही मानती है और उसी संवेदनशीलता के साथ उन्हें पूज्यनीय माना जाता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अभियान के अंतर्गत 3 हजार 90 करोड़ लागत के जल संरक्षण के 990 कार्य आज से प्रदेश में आरंभ हो रहे हैं। प्रत्येक जिले, विकासखंड और पंचायत स्तर पर जल संरचनाओं की मरम्मत, पर्यावरण संरक्षण और पौधरोपण के लिए जनभागीदारी से गतिविधियां संचालित की जाएंगी।

अभियान को रस्म अदायगी न माना जाए

पंचायत मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने कहा कि यह आवश्यक है कि अभियान को रस्म अदायगी न माना जाए। हम सभी जल स्त्रोतों को सहेजने उनकी साफ-सफाई और उनके आस-पास वृक्षारोपण जैसी गतिविधियां जनभागीदारी से सुनिश्चित करें। मंत्री ने कहा कि वे 16 जून तक चलने वाले अभियान में प्रत्येक दिन एक नदी के उद्गम स्थल पर जाकर स्थल के संरक्षण साफ-सफाई और वृक्षारोपण गतिविधियों में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि नदियों के उद्गम स्थल के आसपास बहेड़ा, हर्र, आम, बांस, नीम, बेल आदि के पौधे जल स्त्रोतों को संरक्षित करने और उन्हें समर्थ बनाने में सक्षम हैं अतः इस प्रकार के पौधों के रोपण को प्राथमिकता दी जाए।

केंद्र और राज्यों ने डेटाबेस से अपात्रों को किया बाहर

देश में एक लाख किसानों ने छोड़ी पीएम सम्मान निधि

-बिहार, यूपी-राजस्थान के किसानों की दरियादिली

भोपाल। जागत गांव हमार

देश में किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) का लाभ खुद से छोड़ रहे हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जून 2023 से मई 2024 तक देशभर में 1.16 लाख किसानों ने खुद को पीएम किसान योजना की सूची से बाहर लिया है। यानी ये किसान खुद से पीएम किसान योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं। खास बात यह है कि योजना छोड़ने वाले सूची में बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसान सबसे आगे हैं। बिहार में सबसे ज्यादा 29,176 किसान परिवारों ने पीएम-किसान का लाभ छोड़ा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 26,593 और राजस्थान में 10,343 किसानों ने पीएम किसान योजना का लाभ छोड़ा है। कृषि मंत्रालय ने पिछले साल पीएम-किसान मोबाइल ऐप और वेबसाइट में एक मॉड्यूल पेश किया था, जो किसानों को स्वेच्छा से योजना से बाहर निकलने में सक्षम बनाता है। अधिकारियों ने बताया कि बहुत अधिक जोत वाले किसानों ने खुद से सब्सिडी का लाभ न लेने का फैसला किया। वहीं, कर-भुगतान करने वाले छोटे किसानों ने भी योजना का लाभ लेना छोड़ दिया। किसानों की इस

पीएम किसान के तहत 6000 रुपए

पीएम-किसान पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के अनुसार, अपने लाभ को सरेंडर करने के इच्छुक किसानों को अपना पंजीकरण नंबर दर्ज करना होगा। उसके बाद, वे एक ओटीपी जनरेट कर सकते हैं जो उनके आधार-पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से, पीएम-किसान लाभार्थी की पहचान की जाती है। इसके बाद, लाभार्थी अपने लाभ को सरेंडर कर सकता है। पीएम-किसान योजना के तहत, पात्र किसान परिवारों को हर चार महीने में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से तीन समान किस्तों में 6,000 रुपए प्रति वर्ष मिलते हैं।

लाभार्थियों की संख्या 3.03 करोड़ थी

यह योजना 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 24 फरवरी, 2019 को शुरू की गई थी। दिसंबर-मार्च 2018-19 में पहली किस्त के समय लाभार्थियों की संख्या 3.03 करोड़ थी। पीएम-किसान एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसमें केंद्र से 100 फीसदी वित्त पोषण होता है। यह फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है। अब तक किसानों को पीएम-किसान की 16 किस्तें जारी की जा चुकी हैं।

चौकीदार दे रहे पहरा, पेड़ों का आकार लेते पौधे, अब नहीं बिगड़ेगा पर्यावरण का संतुलन

खंडवा की बंजर जमीन में अब लहलहा रहे 20 हजार पौधे

खंडवा। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। हर साल इसी दिन लाखों की संख्या में लोग पौधा रोपण करते हैं, लेकिन देखरेख के अभाव में अधिकांश पौधे मर जाते हैं। खंडवा का यह नजारा बिलकुल अलग है। यहां लगभग डेढ़ साल पहले नगर निगम एवं जिला प्रशासन ने बंजर जमीनों में विभिन्न प्रजातियों के करीब 20 हजार पौधे लगाए थे। अच्छी बात यह है कि सभी पौधे जीवित हैं और वृक्ष का आकार ले रहे हैं। नगर निगम को 6 महीने कड़ी मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर बंजर जमीन पौधा रोपण के लिए तैयार हो पाई। पौधारोपण के बाद भी उन्हें सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती थी। नगर निगम ने यहां पौधों की देखभाल के लिए दो चौकीदार नियुक्त किए। सिंचाई के लिए ट्यूबवेल तैयार किया, ताकि रोजाना पानी मिल सके। नतीजा आज बंजर पड़ी जमीने हरेभरे जंगल का रूप ले रही हैं। इसी को देखते हुए अब नगर निगम एक एकड़ में फिर एक नया जंगल तैयार करने जा रहा है।

जमीन को तैयार करने में लगे 6 महीने

नगर निगम आयुक्त निलेश दुबे ने बताया कि नवकार नगर में तीन एकड़ में मियावॉकी पद्धति से पौधे लगाकर जंगल तैयार किया है। यहां जमीन पूरी तरह बंजर थी, जिसे तैयार करने में 6 महीने लगे। पौधों को सुरक्षित रखने के लिए ट्यूबवेल के साथ निगरानी के लिए दो चौकीदार तैनात किए। अब यहां सैकड़ों पौधे पेड़ बनकर लहलहा रहे हैं। हालांकि पहले भी निगम में यहां पौधारोपण के प्रयास किए थे, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए, इस बार मियां बाकी पद्धति से पौधे लगाए तो सफलता मिली।

यहां लगाए 3500 पौधे

अफसरों ने बताया कि निगम ने दो साल पहले नागचुर रेस्ट हाउस के पास करीब साढ़े तीन हजार पौधे लगाए थे। अब यहां पौधे पेड़ का रूप लेने लगे हैं। 2 साल में पौधे 8 से 10 फीट ऊंची हो गए हैं। इसके अलावा सुक्ता फिल्टर प्लांट क्षेत्र में डेढ़ साल पहले बंजर जमीन पर करीब 2000 पौधे लगाए थे। लगातार सिंचाई और देखरेख से यहां सभी पौधे जीवित है। इनमें ज्यादातर पौधे आम के है।

यहां लगाएंगे एक हजार पौधे

निगम आयुक्त नीलेश दुबे ने बताया कि शहर का पर्यवारण बेहतर बनाने के लिए तीन अलग-अलग बंजर जमीनों पर पौधारोपण करके उन्हें जंगल बनाया है। तीनों ही जगह सभी पौधे जीवित है। इस सफलता के बाद अब नागचून तालाब के पास एक एकड़ में ऐसा ही एक और जंगल तैयार करेंगे। यहां लगभग 1000 नीम के पौधे लगाएंगे।

अब किसानों को नहीं जलानी पड़ेगी पराली, खेत में खाद बना देगी मशीन

गन्ना, कपास, मक्का, केला जैसी कई फसलों के ठूंठो से छुटकारा पाने के लिए भी कर सकते हैं इस्तेमाल

मध्य प्रदेश सरकार सुपर सीडर मशीन पर दे रही 40 फीसदी तक सब्सिडी

भोपाल। जागत गांव हमार

धान के किसानों के लिए फसल लेने के बाद सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आती है पराली। पंजाब-हरियाणा के किसान फसल लेने के बाद पराली जला देते हैं, जिससे दिल्ली-एनसीआर में हर साल प्रदूषण असहनीय स्तर कर पहुंच जाता है। इसे रोकने के लिए किसानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तक हो जाती है लेकिन फिर भी इसका पक्का समाधान अभी तक नहीं मिल पाया है। हम किसानों को एक ऐसी मशीन के बारे में बताएंगे जो पराली के निपटान के लिए बेहतरीन समाधान है। इस मशीन का नाम है सुपर सीडर। ये मशीन कैसे पराली निपटान में किसानों की मदद करेगी और इसके क्या फायदे हैं, ये सब हम आपको बता रहे हैं। पराली की समस्या से छुटकारा पाने के लिए वैज्ञानिकों ने सुपर सीडर मशीन को विकसित किया है। ये मशीन ना सिर्फ किसानों को पराली जलाने से बचाती, बल्कि उनकी खेती का लागत भी कम करती है। सुपर सीडर असल में तीन मशीनों को जोड़कर एक मशीन बनाई गई है। इसमें एक प्रेस व्हील्स के साथ रोटरी टिलर और सीड प्लांट को जोड़ा गया है। सुपर सीडर का इस्तेमाल धान, गेहूं और चना जैसे बीज बोने के लिए किया जाता है। इतना ही नहीं, सुपर सीडर मशीन का केवल पराली ही नहीं, बल्कि गन्ना, कपास, मक्का, केला जैसी कई फसलों के ठूंठो से छुटकारा पाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता जाता है। असल में सुपर सीडर मशीन एक मल्टी टास्किंग मशीन है। इससे किसान बोवनी, जुताई, मल्चिंग और खाद फैलाने तक का काम एक साथ कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो इस मशीन के इस्तेमाल से खेती के काम बेहद आसान हो जाते हैं।

सुपर सीडर मशीन के फायदे

इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मशीन पराली को बिना जलाए खेत में ही खत्म कर देती है। इसके अलावा सुपर सीडर खेत को तैयार करने में लगने वाला बहुत समय बचा देती है। सुपर सीडर मशीन इस तरह से किसान की लागत भी काफी घटा देती है। सबसे खास बात ये है कि इस मशीन से बीज की बुआई और जमीन की तैयारी एक बार में एकसाथ की जा सकती है। सुपर सीडर मशीन के इस्तेमाल से सबसे कठिन माना जाने वाला पराली प्रबंधन, सबसे आसानी से किया जा सकता है। ये मशीन पराली को जलाने पर होने वाले वायु प्रदूषण से भी बचाती है और जमीन के पोषक तत्व भी नष्ट नहीं होते।

एक घंटे में एक एकड़ तक की पराली नष्ट करने की क्षमता

जब धान या गेहूं की हारवेस्टर से कटाई होती है तो पराली या तो खेत में खड़ी रहती है फिर पड़ी रहती है। सुपर सीडर मशीन इस पराली पर सीधे बिजाई कर सकती है। सुपर सीडर मशीन धान और गेहूं की पराली को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर मिट्टी में मिलाती जाती है। फिर इसके ऊपर से गेहूं या सरसों की बिजाई के लिए सुपर सीडर बीज भी डालता जाता है। ये मशीन एक घंटे में एक एकड़ जमीन में फैली पराली को नष्ट कर देती है और उसके ऊपर से नई बुआई करती है। इस क्रम में मिट्टी में दबी पराली गलकर खाद बन जाती है। इससे होता ये है कि जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है और पैदावार भी अधिक होती है। इतना ही नहीं, इस प्रक्रिया के कारण जमीन पानी भी ज्यादा सोखने लगती है। इस तरह सुपर सीडर मशीन फसलों की बोवनी कर देती है और किसानों को पराली भी नहीं जलानी पड़ती। खेत की उर्वरा शक्ति भी कम नहीं होती।

कीमत और सब्सिडी

सुपर सीडर मशीन के कई सारे मॉडल आते हैं। मास्कीओ गास्पार्दो, केएस ग्रुप, शक्तिमान आदि कुछ लोकप्रिय कंपनियां सुपर सीडर मशीन भारत में बेचती हैं। ये मशीन कई कैटेगिरी में भी उपलब्ध है, उसी हिसाब से इसका दाम तय होता है। सुपर सीडर मशीन का दाम 80,000 रुपए से 2.99 लाख है। हालांकि सुपर सीडर मशीन के लिए कई सारी राज्य सरकारें सब्सिडी भी देती हैं। मध्य प्रदेश सरकार सुपर सीडर मशीन पर 40 फीसदी तक सब्सिडी देती है। वहीं हरियाणा सरकार इस मशीन की खरीद पर 50 फीसदी तक अनुदान देती है और पंजाब सरकार भी इसपर सब्सिडी देती है। इसके अलावा अगर कई किसान मिलकर सोसायटी के जरिए सुपर सीडर खरीदते हैं तो इसपर 80 फीसदी तक सब्सिडी मिल सकती है।

वैश्विक मौसम एजेंसी की निदेशक ने कहा-जलवायु हमें लगातार चिंतित कर रही

मई-2024 दुनिया का सबसे गर्म महीना रहा

फसलों के उत्पादन पर बुरा असर पड़ने का डर

भोपाल। जागत गांव हमार

इस साल 2024 में दुनिया का सबसे गर्म महीना मई दर्ज किया गया है। यूरोपीय यूनियन की संस्था कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने कहा है कि 2024 में दुनिया का सबसे गर्म महीना मई रहा है। इस महीने ग्लोबल एवरेज सरफेस टेंपरेचर 1991-2020 के औसत से 0.65 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। मौसम एजेंसी की निदेशक ने कहा कि पिछले 12 महीनों ने पहले कभी नहीं देखे गए रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसका मुख्य कारण हमारे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और ट्रॉपिकल प्रशांत क्षेत्र में अल नीनो घटना है। अधिकतम वैश्विक तापमान के कारण भारत को कठिन समय का सामना करना पड़ा है और फसलों के उत्पादन पर बुरा असर होने का संकट है। वैश्विक मौसम एजेंसी कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार मई लगातार 12वां महीना रहा जब वैश्विक औसत तापमान ने रिकॉर्ड बनाया। मई 2024 में तापमान मई 2020 में दर्ज कि गए हाईएस्ट तापमान से 0.19 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। मौसम एजेंसी ने कहा कि 2015-16 में पहले भी असामान्य और इसी तरह का मासिक वैश्विक तापमान रिकॉर्ड किया गया था। एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार मई 2024 के लिए वैश्विक औसत तापमान 1850-1900 के औसत से 1.52 डिग्री सेल्सियस अधिक था। यह जुलाई 2023 से लगातार 11वां महीना था जब 1.5 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान रहा। मई 2024 डेटा रिकॉर्ड में किसी भी पिछले मई की तुलना में वैश्विक रूप से अधिक गर्म था, जिसमें औसत सरफेस एयर टेंपरेचर 15.91 डिग्री सेल्सियस था, जो मई 1991-2020 के औसत से 0.65 डिग्री सेल्सियस अधिक था।

पिछले 12 महीनों में सभी रिकॉर्ड टूटे

आंकड़ों से पता चलता है कि जून 2023 से मई 2024 तक पिछले 12 महीनों के लिए वैश्विक औसत तापमान रिकॉर्ड पर सबसे अधिक है। तापमान 1991-2020 के औसत से 0.75 डिग्री सेल्सियस अधिक और 1850-1900 के औसत से 1.63 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की निदेशक सामंथा बर्गेस ने कहा कि जलवायु हमें लगातार चिंतित कर रही है। पिछले 12 महीनों ने पहले कभी नहीं देखे गए रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसका मुख्य कारण हमारे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और ट्रॉपिकल प्रशांत क्षेत्र में अल नीनो घटना है। जब तक वैश्विक उत्सर्जन शून्य नहीं हो जाता तब तक जलवायु गर्म होती रहेगी और रिकॉर्ड तोड़ती रहेगी।

पूरे एशिया में सूखे के हालात

वैश्विक मौसम एजेंसी ने कहा कि पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में तापमान औसत से कम था जो ला नीना के बढ़ने का संकेत देता है। लेकिन, पिछले महीने कई क्षेत्रों में समुद्र के ऊपर हवा का तापमान असामान्य रूप से हाई लेवल पर रहा। मई में समुद्र की सतह का तापमान 20.93 डिग्री सेल्सियस था, जो महीने के लिए रिकॉर्ड पर हाईएस्ट वैल्यू था। यह लगातार चौदहवां महीना था जब स्स्ज्ञ वर्ष के संबंधित महीने के लिए सबसे गर्म था। मौसम एजेंसी ने कहा कि मई में पूरे एशिया में औसत से ज्यादा सूखे के हालात दर्ज किए गए हैं।

फसलों के उत्पादन पर असर

पिछले 12 महीनों में अधिकतम वैश्विक तापमान के कारण भारत को कठिन समय का सामना करना पड़ा है। अधिक तापमान का कारण गर्म पानी की घटना अल नीनो है, जो जून 2023 में उभरी थी। भारत ने दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पूर्व मानसून की कमी का अनुभव किया, इसके अलावा सर्दियों और प्री-मानसून अवधि के दौरान सामान्य से कम बारिश हुई है। इससे फसलों के उत्पादन पर असर पड़ा है।

सीपीसी पद्धति से अफीम के उत्पादन में आई क्रांति

दवा उद्योग में बढ़ रही मंदसौर के अफीम की डिमांड

देश-दुनिया में पहचाने जाने वाले मंदसौर, नीमच क्षेत्र में अफीम की नई किस्म पर शोध किया जा रहा

भोपाल। जागत गांव हमार

गंभीर रोगों में जीवनरक्षक दवाओं को बनाने में काम में आने वाले अफीम के उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाए जाने और अफीम की मादक पदार्थ के रूप में तस्करी पर नकेल कसने की महत्वकांक्षी योजना के तहत अफीम की खेती की नई पद्धति को सीपीएस को प्रायोगिक रूप से भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने लागू किया है। जिसके तहत अब अफीम उत्पाद का क्रय शासकीय केंद्रों पर केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग की निगरानी में कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच किया जा रहा है। इससे यह हुआ है कि अब मंदसौर के अफीम की मांग दवा उद्योग में तेजी से बढ़ी है। गौरतलब है कि अफीम उत्पादन के लिए देश-दुनिया में पहचाने जाने वाले मंदसौर, नीमच क्षेत्र में अफीम की नई किस्म पर शोध किया जा रहा है। मंदसौर, उदयपुर और लखनऊ के कृषि वैज्ञानिक लगातार इस कोशिश में लगे हैं कि मार्फीन का प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा मिलने लगे ताकि विदेशों में भारतीय अफीम की मांग बढ़ सकें। नींद, खांसी सहित अन्य दवाओं के निर्माण के लिए अफीम से प्राप्त उच्च कोटि की मार्फिन की मांग है। इस कसौटी पर आस्ट्रेलिया में उत्पादित होने वाली अफीम सबसे अधिक खरी उतरती है। दुनिया भर में दवा उद्योग आस्ट्रेलिया की अफीम को श्रेष्ठ मानता है। उसके बाद मंदसौर-नीमच व चित्तौड़ की अफीम का नंबर आता है।

लगातार चल रहा शोध

मंदसौर में उत्पादित अफीम की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लगातार शोध हो रहा है। मंदसौर में चल रहे कृषि वैज्ञानियों के शोध से मंदसौर में उत्पादित अफीम को इस तरह तैयार किया जाएगा कि वह इतनी उच्च गुणवत्ता की हो कि दुनिया भर का दवा उद्योग आस्ट्रेलियाई अफीम को टक्कर दे सके। मंदसौर के कैलाशनाथ काटजू उद्यानिकी महाविद्यालय सहित उदयपुर व लखनऊ में कृषि वैज्ञानिक इस तरह के शोध में जुटे हैं। इसमें अफीम के पौधों में फूल के रंगों के आधार पर मार्फिन व कोडीन फास्फेट का प्रतिशत तय किया जा सकेगा।

अमेरिका, जापान में मांग ज्यादा

शोध के तहत डोडा में ज्यादा मार्फिन वाली अफीम के उत्पादन के साथ ही फूलों के रंग से यह पता चल जाएगा कि कौन से पौधे में मार्फिन की गुणवत्ता उच्चतम स्तर की होगी। उन पौधों से निकलने वाले डोडा को दवा उद्योगों के लिए चिह्नित कर लिया जाएगा। आस्ट्रेलिया में अफीम की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए डोडा से कांसन्ट्रेट पापीस्ट्रा पद्धति से अफीम निकाली जाती है। इसी कारण वहां की अफीम की मांग अमेरिका, जापान व अन्य देशों की मेडिकल कंपनियां ज्यादा करती हैं। इसमें डोडा से सीधे अफीम निकालने की प्रक्रिया होती है।

मार्फिन का प्रतिशत 4 से 6 के बीच

भारत में अब तक डोडा से पुरानी पद्धति लुणी-चिरनी से खेत में अफीम निकालने और उसे एकत्र कर नारकोटिक्स विभाग को देने की प्रक्रिया चल रही है। नारकोटिक्स विभाग नीमच व गाजीपुर में स्थित अल्केलाइड फैक्ट्री में इस अफीम को प्रोसेस कर कोडीन फास्फेट, मार्फिन व अन्य उपयोगी उत्पाद अलग-अलग करता है। इस पुरानी पद्धति से मार्फीन का प्रतिशत 4 से 6 के बीच होने की वजह से दवा कंपनियां मंदसौर की अफीम का उपयोग कम करती हैं।

सीपीएस पद्धति में मिल रहे अच्छे परिणाम

अब नई पद्धति से क्षेत्र के अफीम उत्पादक किसानों को नया बाजार मिलने की संभावना है। पहले अफीम की फसल में केवल गुलाबी रंग के फूल आते थे। कृषि वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं और अभी तक जो अफीम की किस्मे बनाई हैं, उनमें फूलों का रंग भी सफेद हो गया है। और शोध केंद्र पर तो अफीम में मार्फीन 15 प्रतिशत तक मिलने लगी है। जबकि खेतों में यह 10 से 12 प्रतिशत तक मार्फीन मिल रही है। नई अफीम नीति में केंद्र सरकार ने मार्फिन का 4.2 किग्रा प्रति हेक्टेयर से अधिक का औसत देने वाले किसानों को ही परंपरागत खेती के लिए पट्टे दिए हैं।

6-6 आरी के हरे पट्टे दिए गए

वहीं एक नया प्रयोग करने के लिए 3.7 से 4.2 प्रतिशत तक औसत वाले अपात्र किसानों को सीपीएस पद्धति में 6-6 आरी के हरे पट्टे दिए गए हैं। यह किसान पूरे डोडे नारकोटिक्स विभाग को सौंपे रहे हैं। इन डोडो से बिना चिराई के सीपीएस पद्धति से अफीम निकाली जा रही। भारत में यह पहली बार हो रहा है।

मंदसौर के साथ ही उदयपुर और लखनऊ में भी अफीम फसल में थीबेन व मार्फीन का प्रतिशत बढ़ाने का शोध चल रहा है। इसमे नई किस्मों में फूलों का रंग भी बदल रहा है। पहले पिंक फूल होते थे, अब सफेद हो गए है इसमें मार्फीन का 10 से 12 प्रतिशत तक मिल रहा है। सीपीएस पद्धति में इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे।

डॉ. आरएस चुंडावत, वैज्ञानिक
केएनके उद्यानिकी महाविद्यालय

पौधों की सेहत पर भी नहीं पड़ेगा बुरा असर

दमोह हमें फसलों के लिए अमृत 'जहर' अब बढ़ेगा उत्पादन

दमोह। जागत गांव हमार

किसानी में कई चुनौतियां हैं। खासकर फसलों में लगने वाले कीड़े ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में किसान भाई तरह-तरह के केमिकल युक्त कीटनाशक का उपयोग करते हैं, जिसका साइड इफेक्ट पौधों की सेहत पर भी पड़ता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे देसी कीटनाशक के बारे में बताते हैं, जो किसी जहर से कम नहीं, लेकिन फसलों के लिए अमृत जैसा काम करता है। कीटों को मारने के साथ उत्पादन भी बढ़ाता है। बुंदेलखंड में कृषि कार्य में लगी महिलाएं इस देसी कीटनाशक को तैयार करती हैं। बड़े पैमाने पर इसकी बिक्री होती है। मप्र के कटनी जिले की मानव जीवन विकास समिति के लोग दूर दराज ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर निरंतर इसी कीटनाशक को बनाने का काम करते हैं। दमोह के जबेरा ब्लॉक के भिनेनी गांव में भी समिति के लोग जैविक कीटनाशक बना रहे हैं। इससे किसानों को तो फायदा है ही महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है।

महिलाओं को मिल रहा रोजगार

एमजेवीएस से जुड़ी महिला हरी बाई गौंड ने बताया कि बदलते दौर के साथ किसान अधिक फसल उत्पादन के लिए तरह-तरह के प्रयोग कर रहे हैं। फसलों में लगने वाले कीटों को खत्म करने के लिए निरंतर रासायनिक दवाओं का छिड़काव मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी क्षीण कर रहा है। इस समस्या के निदान के लिए मानव जीवन विकास समिति द्वारा जैविक कीटनाशक दवा बनाने का काम किया जा रहा है। इसमें स्व सहायता समूह की महिलाओं को भी जैविक कीटनाशक दवा बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

किसान भी बना सकते हैं कीटनाशक

समिति के ब्लॉक प्रभारी राकेश विश्वकर्मा ने बताया कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे विषैले औषधीय पौधे हैं, जिनका सेवन पालतू जानवर नहीं करते हैं। इनके पत्तों को हम इस प्रयोगशाला में इकट्ठा करते हैं, फिर उचित मात्रा में लेकर खलबट्टे में कुचला जाता है। इन पत्तों को कुचलने के बाद मिले रस को गौमूत्र के साथ उबला जाता है। तब जैविक कीटनाशक दवा बन पाती है, जो रासायनिक दवा के मुकाबले सस्ता भी है।

पंप की मदद से छिड़काव

जैसे कुछ महीनों पहले किसानों ने चने की फसल बोई थी, जिसमें इल्लियां, कीट लग गए थे। इनको खत्म करने के लिए समिति की महिलाओं ने जैविक कीटनाशक दवा बनाई। इसका पंप की मदद से छिड़काव करने से कीट-पतंगे नष्ट हो गए थे। फसल को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा था।

इतनी बार करें छिड़काव

किसान हर 15 दिनों पर एक बार इस दवा का छिड़काव खेत में करें। यह प्रक्रिया तब तक करें, जब तक फसल पककर कट नहीं जाती। इस दवा के छिड़काव से इल्लियां तो खत्म होंगी ही, फसल को भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। कम से कम तीन बार तो इस दवा का छिड़काव फसलों पर अनिवार्य है।

खाद्य निर्धनता के गंभीर स्तर का शिकार हर चौथा बच्चा

गरीब की थाली से गायब होता पोषण अपने आप में एक बड़ी समस्या है। वहीं जब बात बच्चों की हो तो यह किसी संकट से कम नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी की आज पांच वर्ष या उससे कम आयु का हर चौथा बच्चा खाद्य निर्धनता के गंभीर स्तर का शिकार है। मतलब की दुनिया में पांच वर्ष से कम आयु के 18.1 करोड़ बच्चे इस समस्या से जूझ रहे हैं। देखा जाए तो यह वो बच्चे हैं, जिनके पास पर्याप्त पोषण युक्त आहार उपलब्ध नहीं या फिर उनके आहार में पर्याप्त विविधता की भी कमी है। इनमें 65 फीसदी बच्चे हैं जो केवल 20 देशों में रह रहे हैं। हैरानी की बात है कि इन देशों में भारत भी शामिल है।

दुनिया में खाद्य निर्धनता से जूझ रहा हर चौथा बच्चा, आंकड़ों के मुताबिक इनमें 6.4 करोड़ बच्चे दक्षिण एशियाई देशों में रह रहे हैं, जबकि सब सहारा अफ्रीका इनमें से 5.9 करोड़ बच्चों का घर है। भारत की बात करें तो स्थिति कहीं ज्यादा नाजुक है, जहां 76 फीसदी बच्चे इस समस्या से जूझ रहे हैं। गौरतलब है कि भारत में जहां 40 फीसदी बच्चे अपने जीवन के शुरूआती वर्षों में गंभीर खाद्य निधज्ञता से जूझ रहे हैं, वहीं 36 फीसदी बच्चे ऐसे हैं जो इस खाद्य निधज्ञता के मध्यम स्तर का सामना करने को मजबूर हैं।

देखा जाए तो गंभीर खाद्य निर्धनता का सामना करने वाले इन बच्चों के जानलेवा कुपोषण (वेस्टिंग) से पीड़ित होने की आशंका 50 फीसदी तक अधिक होती है। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) द्वारा जारी नई रिपोर्ट 'चाइल्ड फूड पावर्टी: न्यूट्रिशन डेप्रिवेशन इन अर्ली चाइल्डहुड' में सामने आई है। यह रिपोर्ट दुनिया के करीब 100 देशों में रहने वाले बच्चों में पोषक आहार की कमी, उसके प्रभावों और कारणों को उजागर करती है। सवाल यह है कि इस खाद्य निर्धनता को कैसे परिभाषित किया जाए? यूनिसेफ के मुताबिक जब बच्चों को शुरूआती वर्षों में स्वस्थ, पोषण और विविधता से भरपूर पर्याप्त आहार नहीं मिल पाता, तो उस स्थिति को खाद्य निर्धनता के रूप में जाना जाता है।

इसमें कोई शक नहीं की जीवन के शुरूआती वर्षों में बच्चों के पर्याप्त मानसिक और शारीरिक विकास के लिए सेहतमन्द पौष्टिक आहार बेहद जरूरी होता है, मगर मौजूदा समय में दुनिया के कई हिस्सों में बढ़ती महंगाई के चलते खाद्य पदार्थों की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल आया है। इतना ही नहीं जीवन यापन की बढ़ती लागत आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रही है। नतीजन दुनिया में लाखों माता-पिता अपने बच्चों को पौष्टिक आहार देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

वहीं कई देश ऐसे भी हैं जो अब भी महामारी के असर से पूरी तरह नहीं उबरे हैं। जलवायु परिवर्तन और विषम परिस्थितियों के चलते स्थिति बद से बदतर होती जा रही है।

कई देशों में पोषण तो दूर की बात बच्चों को भरपेट भोजन भी नहीं मिल रहा। इसकी वजह से न केवल यह बच्चे बल्कि उनके परिवार भी गरीबी और अभावों के भंवर जाल में फंस जाते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, खाद्य निर्धनता के कुल मामलों में से करीब आधे ऐसे परिवारों में दर्ज किए गए हैं जो पहले ही गरीबी से जूझ रहे हैं।

सिर्फ कमजोर परिवारों तक सीमित नहीं गरीबी: बाजारों में स्वास्थ्य के लिहाज से हानिकारक खाद्य पदार्थों की बढ़ता बोलबाला भी इसके पीछे की एक वजह है। ऊपर से खाद्य कंपनियों जिस तरह से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले खाद्य पदार्थों की मार्केटिंग कर रही हैं वो भी बच्चों को खाद्य निर्धनता

के दलदल में धकेल रहा है। देखा जाए तो बढ़ते बाजारीकरण ने सबके हाथों में फास्ट-फूड तो दिया लेकिन पोषण छीन लिया।

इसके साथ ही बच्चों को पोषक, सुरक्षित आहार उपलब्ध कराने के लिए बनाई खाद्य प्रणालियों की विफलता भी इसके लिए जिम्मेवार है। इसके साथ ही बच्चों के आहार के जरूरी तौर-तरीकों पर ध्यान न रख पाना भी इस समस्या को बढ़ा रहा है। इस रिपोर्ट में खाद्य निधज्ञता को वर्गीकृत करने का जो आधार है वो खाद्य पदार्थों के सेवन पर आधारित है। उदाहरण के लिए जब बच्चे हर दिन आठ में से दो या उससे कम खाद्य समूहों का सेवन करते हैं तो उसे गंभीर खाद्य निर्धनता के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इस स्थिति में हर पांच में से चार बच्चों को केवल मां का दूध, चावल, मक्का या गेहूं जैसे स्टार्चयुक्त आहार दिए जाते हैं। इनमें से 10 फीसदी से भी कम बच्चों को फ्ल और सब्जियां दी जाती हैं। वहीं पांच फीसदी से भी कम बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें आहार में अंडे, मछली, मुर्गी या मांस जैसे पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ खिलाए जाते हैं।

इसी तरह हर दिन तीन से चार खाद्य समूहों का सेवन करने वालों को मध्यम श्रेणी में जबकि पांच या उससे अधिक खाद्य समूहों का सेवन करने वाले बच्चों के बारे में यह माना गया है कि वो खाद्य निर्धनता का सामना नहीं कर रहे हैं।

यूनीसेफ के पोषण विशेषज्ञ हैरियट टॉरलेस्सी, ने यूएन न्यूज को बताया कि दुनिया भर में हर चौथा बच्चा पोषण के लिहाज से बेहद खराब आहार पर निर्भर है, और वो खाद्य समूहों में से केवल दो या उससे कम का ही सेवन कर पा रहा है।

उन्होंने अफगानिस्तान का उदाहरण देते हुए कहा है कि वहां एक बच्चा पूरे दिन में कुछ ब्रेड या किस्मत अच्छी हो तो दूध का ही सेवन कर पाता है। फल और सब्जियों का थाली में होना भी किसी आश्चर्य से कम नहीं। वहीं पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का भी कोई स्रोत नहीं है। उनके मुताबिक यह बेहद परेशान कर देने वाला है, क्योंकि बच्चे इस खराब आहार पर जीवित नहीं रह सकते।

रिपोर्ट में हिंसक टकरावों और प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे सोमालिया का जिक्र करते हुए लिखा है कि वहां 63 फीसदी बच्चे, गंभीर खाद्य निर्धनता से जूझ रहे हैं। इसी तरह गाजा में जारी जंग ने भी 90 फीसदी बच्चों के लिए खाद्य निर्धनता के स्तर को बढ़ा दिया है।

रिपोर्ट के मुताबिक यह आपदाएं और संघर्ष जिस तेजी से बच्चों को खाद्य निर्धनता में धकेल रही हैं, उससे बच्चों में कुपोषण का जोखिम बढ़ रहा है। साथ ही उनके जीवन पर भी खतरा मंडराने लगा है। यूनिसेफ ने इस बात की भी पुष्टि की है कि जिन देशों में कुपोषण की दर अधिक है, वहां बच्चों में खाद्य निर्धनता का गंभीर स्तर तीन गुना अधिक आम है।

भारत में भी हम भले ही विकास के जितने चाहे दावे कर ले लेकिन सच यही है कि पोषण युक्त आहार अब आम आदमी की जेब से दूर होता जा रहा है। दूध, दालों, सब्जियों और फ्लों की बढ़ती कीमतें इस बात का जीता जागता सबूत हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या खाने की थाली से दूर होता यह

पर्यावरण दिवस पर ही वृक्षारोपण का नाटक क्यों?

डॉ राजाराम त्रिपाठी
पर्यावरणविद, अखिल भारतीय किसान महासंघ आईफा के राष्ट्रीय संयोजक

देश में दशकों की वृक्षारोपण नौटंकी के बावजूद प्रति व्यक्ति सिर्फ 28 पेड़ बचे हैं, जबकि विश्व में सबसे गरीब देशों में शुमार इथोपिया हरित-संपदा के मामले में प्रति व्यक्ति 143 पेड़ों के साथ हमसे 5 गुना अधिक समृद्ध है। आजादी के बाद से अब तक हमने देश में जितने भी पौधे लगाए, अगर उनमें से 50 फीसदी भी जिंदा होते और जंगल बचाए जाते तो हरित संपदा में हम दुनिया में नंबर एक होते। डेढ़ दो महीने की चुनावी कवायद के बाद देश की सरकार बनने की आपाधापी के दरमियां 5 जून को विश्व पयाज्वरण दिवस कब दबे पाँव आया और निकल लिया, यह आम जनता को तो पता भी नहीं चला।

हम स्वयं पिछले 30 वर्षों से पेड़ लगा रहे हैं पर आज तक यह नहीं समझ पाए कि हमारे देश के किस विद्वान के दिमाग की उपज थी कि यहाँ विश्व पर्यावरण दिवस पाँच जून के दिन ही वृक्षारोपण किए जाएं। जबकि विशेषज्ञों का मत है कि असिंचित क्षेत्रों में वृक्षारोपण का आदर्श समय जुलाई अगस्त होना चाहिए। अब चूंकि यह रिवाज बन गया है इसलिए शासकीय कार्यालयों में स्कूलों में अधिकारीगण, नेता गण,शिक्षक, बच्चे सभी हर 5 जून को वृक्षारोपण कर रहे हैं, वन विभाग इसमें सबसे आगे है। देश के ज्यादातर हिस्सों में अभी भी नौतपा का ताप उतरा नहीं है कई स्थानों पर लू चल रही है। लू से बचने के तमाम तरीकों की जानकारी रखते हुए पढ़े लिखे जानकार व्यक्ति भी तमाम डॉक्टरों के रहते भी मौत के मुँह में समा रहे हैं; ऐसी हालात में 5 जून को लगाए गए ये नन्हे पौधे 48 घंटे भी जिंदा रह पाएंगे यह कहना कठिन है। यह स्थापित तथ्य है कि भारत में मॉनसून आम तौर पर 15 जून के बाद ही सक्रिय हो पाता है। पर पयाज्वरण दिवस के नाम पर सरकारी वृक्षारोपण की खानापूर्ति 5 जून को ही होना जरूरी है।

इस काम में हमारे वन विभाग हर साल सबको पीछे छोड़ देते हैं। वन विभाग को इसमें सबसे आगे होना भी चाहिए। क्योंकि देश के हजारों साल पुराने और जैव विविधता से समृद्ध लगभग सभी जंगलों को तो इन्होंने काट कर, कटवा कर,बेंच बांचकर कर फूंक-ताप लिया हैं। इनकी सफाई पसंदगी का यह आलम है कि जंगलों में ठूंठ तक नहीं छोड़ा गया है ।

इधर कुछ दशकों से वृक्षारोपण नामक नए चारागाह को जंगलों की रक्षा के नाम पर बनी ये बाडें निर्द्वंद्व भाव से चट करते जा रही हैं। हर साल नवीन वृक्षारोपण, पुराने वनों के सुधार, पड़ती भूमि संरक्षण आदि तरह-तरह की योजनाएं बनाकर सरकार से जनता के पैसे लो, वृक्षारोपण की नौटंकी करो, फिर भगवान से दुआ करो कि सारे पौधे मर जाएं। अगले साल फिर योजना बनाओ फिर पैसे लो फिर वृक्षारोपण की नौटंकी करो। यही इस साल भी होना है। अब तक सारे महानुभाव वृक्षारोपण की फेटो खिंचवा कर सोशल मीडिया पर लगा चुके हैं,बस किसी तरह समाचार में यह छप जाए कि अमुक महानुभाव ने पौधा रोपकर देश के पर्यावरण पर और देश पर भारी भरकम एहसान कर दिया है, अब आगे पौधा और उसकी किस्मत जाने।

हमारे देश में सरकारी वृक्षारोपण की हालत यह है कि आजादी के बाद वृक्षारोपण कर जितने पौधे लगाए गए उनमें से 50 प्रतिशत भी अगर जिंदा रह जाते तो भारत विश्व में सबसे हरा भरा देश होता। ऐसा लगता है कि हमारे नीति निर्माता नेता गण, अधिकारी गण इतने दूरदर्शीज हैं कि वो जानबूझकर 5 जून को ही वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न कर डालते हैं ताकि पौधा एक हफ्ता से ज्यादा जिंदा ही ना रह पाए।

1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) द्वारा स्थापित, डब्ल्यूईडी ने पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में बनाने का निश्चय लिया। 1973 से हम इसे लगातार मना रहे हैं और हर साल पर्यावरण की रक्षा के लिए तमाम लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, जिस पर हर देश से पूरे वर्ष प्राथमिकता के आधार पर ठोस काम की अपेक्षा की जाती है। सऊदी अरब 2024 के पर्यावरण दिवस समारोह की मेजबानी कर रहा है। पर्यावरण की रक्षा के लिए इस साल भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देश बहुउद्देशीय योजनाओं पर काम कर रहे हैं। हम इसमें क्या क्या कर रहे हैं यह सोचने का अलग विषय है। हमारे देश में पर्यावरण रक्षा के नाम पर केवल पेड़ लगाने की नौटंकी की जाती है।

पेड़ों के मामले में सबसे धनी देश कनाडा में प्रति व्यक्ति पेड़ों की संख्या 10163 है, वहीं हमारे देश में प्रति व्यक्ति मात्र 28 पेड़ बचे हैं। विश्व में सबसे गरीब देशों में शुमार किए जाने वाला देश इथोपिया भी हरित संपदा के मामले में प्रति व्यक्ति 143 पेड़ों के साथ हमसे 5 गुना ज्यादा समृद्ध है। पर्यावरण दिवस की खानापूर्ति करने के लिए हमने भी एक और पीपल का पेड़ अपने इथनो मेडिको हर्बल गार्डन में लगाया है। पीपल ही क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि 'अश्वत्थ: सर्ववृक्षाणां' यानी कि पेड़ों में मैं पीपल हूँ ।

खैर हमने जो पीपल का पौधा रोपा है, वह तो हम हर हाल में जिंदा रख लेंगे पर क्या आप सभी महानुभाव जिन्होंने इस 5 जून को पौधों का रोपण किया है, क्या ईमानदारी से वादा करेंगे कि आपने इस बार जितने पौधे रोपे हैं उन्हें हर हाल में आप जिंदा रखेंगे? अगर आपका जवाब ईमानदारी से हाँ में है तो मेरी ओर से आप सात तोपों की सलामी कुबूल करें। समाचार पत्रों में जब आप 5 जून पर्यावरण दिवस और माननीयों के फोटो देखें तो एक बार सोचिएगा जरूर कि फोटो में दिख रहा नन्हा मुन्ना पौधा कम से कम अगले पर्यावरण दिवस तक ज़िंदा रहेगा अथवा नहीं इसकी गारंटी कौन देगा? सोचिएगा जरूर।

फिश फर्टिलाइजर और इसके द्वारा होने वाले फायदे

फिश फर्टिलाइजर पूरी मछली, उसकी हड्डियों और त्वचा से तैयार होता है। ऐसी मछलियां जिनका कोई प्रयोग नहीं हो पाता है, उन्हें बर्बाद होने की जगह आप बगीचे के लिए पोषक तत्वों में इन्हें बदलकर प्रयोग कर सकते हैं। इस उर्वरक में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं जो पौधों की जड़ों को फायदा पहुचाते हैं। मछली से बनी खाद न सिर्फ आपके पौधों को बढ़ाती है बल्कि यह आपकी मिट्टी को भी मदद करती है।

मछली के बारे में अभी तक आपने सुना होगा कि यह सिर्फ खाने के काम आ सकती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका उपयोग खाद के तौर पर भी होता है। जी हां, कई दशकों पहले जब वैज्ञानिकों ने मिट्टी के लिए जरूरी उर्वरकों की तलाश नहीं की थी तो अमेरिकर में लोग उर्वरक के तौर पर मछली का प्रयोग करते थे। उस समय मूल अमेरिकी नागरिकों ने मक्का उगाने के लिए जमीन तैयार करते समय मिट्टी में एक छोटी सी मछली को रखा। उन्होंने मछली पर ताजी मिट्टी डालकर मक्के के बीज बो।. कहते हैं कि पूरे मौसम के दौरान, मछलियां धीरे-धीरे सड़ती रहीं, फसल को पौष्टिक तत्व मिलते रहे। इसे आज फिश फर्टिलाइजर के तौर पर जाना जाता है। दुनिया के कई हिस्सों में इसका प्रयोग होता है।

कैसे होता है तैयार: फिश फर्टिलाइजर पूरी मछली, उसकी हड्डियों और त्वचा से तैयार होता है। ऐसी मछलियां जिनका कोई प्रयोग नहीं हो पाता है, उन्हें बर्बाद होने की जगह आप बगीचे के लिए पोषक तत्वों में इन्हें बदलकर प्रयोग कर सकते हैं। इस उर्वरक में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं, जो पौधों की जड़ों को फायदा पहुंचाते हैं। मछली से बनी खाद न सिर्फ आपके पौधों को बढ़ाती है बल्कि यह आपकी मिट्टी को भी मदद करती है। इस खाद में मौजूद कार्बनिक पदार्थ मिट्टी की संरचना को बेहतर बनाता है, जिससे यह पानी को बेहतर तरीके से रोक सकती है और आसानी से सांस ले सकती है।

यह उर्वरक मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाकर पौधों की ताकत और शक्ति को बढ़ाता है। वहीं मिट्टी में मौजूद कवक और बैक्टीरिया पोषक तत्वों को तोड़कर उन्हें पौधों की जड़ों तक सही तरह से पहुंचाते हैं। फिर मिट्टी को ढीला करते हैं। पौधों की जड़ें इस हल्की, हवादार मिट्टी में तेजी से और मजबूत होती हैं जो जीवन से भरपूर होती है। कई तरह की प्रक्रियाओं के बाद इसे लिक्विड में बदला जाता है और यह बाजार में आसानी से उपलब्ध होती है।

क्या होता है इसका फायदा: फिश फर्टिलाइजर मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करता है। साथ ही यह पौधों को पनपने के लिए जरूरी पोषक तत्व प्रदान करके मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ाता है। इसमें फास्फोरस और पोटेशियम जैसे बाकी पोषक तत्वों के साथ-साथ नाइट्रोजन भी मौजूद होता है। सिंथेटिक उर्वरकों से अलग ये कैल्शियम जैसे द्वितीयक पोषक तत्व भी प्रदान कर सकते हैं। फिश फर्टिलाइजर का प्रयोग आप सब्जियों, जड़ी-बूटियों, जामुन, बारहमासी, गुलाब और बेल के पौधों के लिए कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने दी गेल की परियोजना को मंजूरी, परियोजना में 60 हजार करोड़ का निवेश होगा

आष्टा में होगा देश का सबसे बड़ा एथेन क्रैकर परियोजना सह पेट्रोकेमिकल परिसर

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा सीहोर जिले की आष्टा तहसील में लगाई जाने वाली देश की सबसे बड़ी एथेन क्रैकर परियोजना को स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आशा व्यक्त की कि इस परियोजना से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और प्रदेश के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने परियोजना के लिए आवश्यक भूमि आवंटन की शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि सीहोर जिले की आष्टा तहसील में लगभग 60 हजार करोड़ रुपए के निवेश से निर्मित होने वाली यह परियोजना देश की सबसे बड़ी एथेन क्रैकर परियोजना होगी। इस परियोजना में ग्रीन फील्ड पेट्रोकेमिकल परिसर भी प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत एलएलडीपीई, एचडीपीई, एमईजी और प्रोपेलीन जैसे पेट्रोकेमिकल्स का उत्पादन होगा। इस परियोजना से निर्माण अवधि के दौरान 15,000 व्यक्तियों तथा संचालन अवधि के दौरान लगभग 5,600 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। परियोजना में 70 हेक्टेयर की टाउनशिप भी प्रस्तावित है। परियोजना का भूमिपूजन आगामी फरवरी तक तथा वाणिज्यिक उत्पादन वित्त वर्ष 2030-31 में प्रारंभ होने की संभावना है। मध्य प्रदेश भवन में आयोजित बैठक में मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध संचालक चंद्रमौली शुक्ला और गेल लिमिटेड के निदेशक आरके सिंघल उपस्थित रहे।

मंत्री विजय शाह ने किया पांच दिवसीय महुआ महोत्सव का शुभारंभ, बोले

महुआ महोत्सव संस्कृति, कला और व्यंजनों से परिचित कराने का प्रयास

भोपाल। जागत गांव हमार

जनजातीय जीवन, देशज ज्ञान परम्परा और सौन्दर्यबोध एकाग्र मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के ग्यारहवें वर्षगांठ समारोह का महुआ महोत्सव के रूप में शुभारंभ हुआ। मंत्री विजय शाह ने कहा कि महुआ महोत्सव जनजातीय संस्कृति, कला और व्यंजनों से परिचित कराने का प्रयास है। जनजातियों के सामाजिक जीवन-शैली और अनुभव को वास्तविक बनाने के लिए बड़े बड़े आर्किटेक्ट के बजाय जनजातीय कलाकारों ने संग्रहालय स्वयं अपने हाथों से बनाया गया है। मंत्री ने प्रदेश और देश के संस्कृति प्रेमियों और पर्यटकों को जनजातीय संग्रहालय आने के लिए आमंत्रित किया। शाह ने संग्रहालय में नव-निर्मित जनजातीय आवास एवं लौह शिल्प का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर संचालक, संस्कृति संचालनालय एनपी नामदेव एवं निदेशक, जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी डॉ. धर्मेंद्र पारे, जनजातीय संग्रहालय संग्रहाध्यक्ष अशोक मिश्र एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इसके पहले महोत्सव में दोपहर 2 बजे से शिल्प एवं व्यंजन मेला, बच्चों के लिए कठपुतली प्रदर्शन एवं जनजातीय नृत्यों की प्रस्तुतियां संयोजित की गई।

नव-निर्मित जीवंत जनजातीय आवास

जनजातीय समुदाय की जीवन शैली को समझने और उसे करीब से देखने के लिए प्रदेश की प्रमुख जनजातियों गोंड, भील, बैगा, कोरकू, भारिया, सहरिया और कोल के सात आवास बनाए गए हैं। इन घरों में जनजातियों के परिवार रहेंगे। इन आवासों के माध्यम से दर्शक और पर्यटक को जनजातीय समुदायों के व्यंजन और उनकी कला को देखने का अवसर भी मिलेगा। इन आवास में अनाज रखने की कोठी, खाट, रोज उपयोग में आने वाली सामग्री और रसोई विशेष रूप से रखी गई है।

विभिन्न राज्यों का कौशल प्रदर्शित

शिल्प मेले में दोपहर 2 बजे से विभिन्न राज्यों के शिल्पों के प्रदर्शन एवं विक्रय किया जा रहा है। मेले में पांच राज्यों के पारंपरिक शिल्पियों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें बांस, धातु, कपड़ा, ज्वैलरी, खराद एवं अन्य शिल्प शामिल हैं। वहीं व्यंजन मेले में भी मध्यप्रदेश के साथ ही गुजरात, उड़ीसा, मणिपुर के व्यंजनकारों द्वारा सुस्वादु व्यंजनों का प्रदर्शन सह-विक्रय किया जा रहा है।

अन्य राज्यों के नृत्यों की प्रस्तुतियां

महुआ महोत्सव अंतर्गत 7 से 10 जून तक प्रतिदिन शाम 6.30 बजे से मध्यप्रदेश के लोक संगीत के साथ-साथ गुजरात, तेलंगाना, उड़ीसा एवं मणिपुर राज्यों की विभिन्न नृत्य प्रस्तुतियां संयोजित की जाएंगी।

अधिष्ठाता प्रोफेसर एसके त्रिपाठी ने फल अनुसंधान केंद्र का किया निरीक्षण, बोले

विंध्य में जलवायु अनुरूप फलों की प्रजातियों का विकास हो

रीवा। जागत गांव हमार

कृषि महाविद्यालय रीवा के अधिष्ठाता डॉ. एसके त्रिपाठी के द्वारा अखिल भारतीय समन्वित फल अनुसंधान परियोजना आईसीएआर बेंगलूरू के अंतर्गत फल अनुसंधान केंद्र रीवा में आम और अमरूद में चल रहे अनुसंधान कार्य का वैज्ञानिकों के साथ निरीक्षण किया। प्रो. त्रिपाठी ने परियोजना के इनचार्ज एवं उद्यान वैज्ञानिक डॉ. टीके सिंह से आम और अमरूद में हो रहे अनुसंधान कार्य के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी हॉसिल की, जिसमें वैज्ञानिक द्वारा बताया गया कि इस समय आम की 237 प्रकार की प्रजातियां लगी हैं, जिसमें नई नई प्रजातियों का विकास, पोषक तत्व प्रबंधन, कीट एवं रोग प्रबंधन पर ट्रायल चल रहे है। इसमें प्रमुख रूप से जीआई टैग से प्रमाणित सुंदरजा, लंगड़ा, दशहरी, आम्रपाली, चौंसा, इरवीन, मल्लिका, बॉम्बे ग्रीन, तोतापरी, कृष्ण भोग, नीलम फजली इत्यादि हैं। परियोजना में कार्य कर रहे पौध सरंक्षण वैज्ञानिक डॉ. अखिलेश कुमार ने अधिष्ठाता को बताया कि फलों में लगने वाले कीट एवं रोग का प्रबंधन पर भी अनुसंधान कार्य चल रहा है। डॉ. कुमार ने कहा कि पिछले तीन वर्षों से मधुमक्खी बॉक्स गौर (फूल की अवस्था) के समय रखा जा रहा है, जिससे देखा जा रहा है कि 15 प्रतिशत तक आम का उत्पादन साथ ही साथ आम की गुणवत्ता में वृद्धि हो रही है। इस अवसर पर कुठलिया प्रक्षेत्र इंचार्ज प्रो. यसएम कुर्मवंशी उपस्थित रहे और अपना मार्गदर्शन दिया। परियोजना में कार्यरत प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी सुधीर सिंह द्वारा किए जा रहे कार्यों को अधिष्ठाता को अवगत कराया। निरीक्षण और भ्रमण के उपरांत अधिष्ठाता ने वैज्ञानिकों की टीम द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि विंध्य क्षेत्र के जलवायु के अनुरूप फलों की प्रजातियों का विकास हो, जिससे यहां के किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले।

धरती और संगीत लौह शिल्प

मध्यप्रदेश की लगभग सभी जनजातियों में यह मान्यता है कि कभी इस सृष्टि में जल प्रलय हुआ था। जल से धरती को निकालने के लिए महादेव ने कौए से कहा कि मिट्टी खोज कर ले आओ। कौआ उड़ता हुआ धरती की खोज में भटकता रहा। उसे केंचुए की याद आई कि उसके पास तो मिट्टी अवश्य होगी। कौए ने केकड़े से मिट्टी लाने को कहा। केकड़े ने केंचुए से मिट्टी लेकर कौए को दी। कौए ने वह मिट्टी महादेव को सौंपी। महादेव ने उस मिट्टी का गोला बनाकर जल के ऊपर रख दिया, वह मिट्टी ही यह धरती है, फिर धरती पर जीवन आया। सबसे पहले मछली के रूप में, फिर पेड़ और पौधे। इन्हीं पेड़ और पौधों से सारा संगीत और नृत्य उपजा। इसी प्रकृति की गाथा को केन्द्र में रखकर लौह शिल्प का प्रदर्शन किया गया है।

रंग लाई पिता पुत्र की मेहनत, अन्य किसानों के लिए बने आदर्श

700 से अधिक पौधे लगा पथरीली जमीन में फला दी हरियाली

टीकमगढ़। जागत गांव हमार

प्रदूषण को लेकर जहां ज्यादातर लोग सिर्फ चिंता जताने तक ही सीमित हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी खामोशी से प्रकृति को नव जीवन देने में लगे हैं। ऐसे ही लोगों में से एक हैं मगरा गांव के करन सिंह और पिता बैजनाथ लोधी। इन दोनों से अपने जज्बे से ककरीली और बंजर भूमि में हरियाली फैली दी। अब तक यहां पर छह साल में 700 से अधिक पौधे लगा चुके हैं। किसान करन सिंह का कहना था कि पहाड़ी क्षेत्र की बंजर और ककरीली भूमि होने से रबी सीजन की फसलों को उगाना सिर्फ मन बहलाने जैसा था। पहाड़ी होने से इस पर खेती करना काफी मुश्किल था। छह साल में इस बंजर जमीन में हरियाली बिखेर दी और मैदान को बगीचा का रूप दे दिया। आज इन पेड़ों से फल भी मिलना शुरू हो गया है। साल के 365 दिनों में हर रोज 12 घंटों की सेवा पर्यावरण संवारने के लिए करते हैं।

किसान बैजनाथ सिंह लोधी बताते हैं कि बंजर पड़ी जमीन पर कोई भी फसल नहीं उगा पाते थे। बोवनी के बाद उसका आकार छोटा ही रहता था। डूडा गांव निवासी मनोहर सिंह लोधी ने बंजर जमीन में पर्यावरण संरक्षण पौध रोपने की प्रेरणा दी। छह साल में 700 से अधिक कई प्रकार के पेड़ों की संख्या हो गई हैं। जिसमें सबसे अधिक

अमरूद, नीबू, कटहल, सागौन, नीम के साथ अन्य पौधे पेड़ बन गए हैं। पिछले पानी खत्म हो गया था, जिससे पेड़ सूखने लगे थे, बालिटयों में पानी भरकर पौधों को सींचा, उसके बाद आज यह बंजर जमीन हरियालीदार दिखाई दे रही हैं। पहले मैदान दिखाई देता था, आज जंगल की तरह दिखाई दे रहा हैं। अब सिंचाई के लिए बोर का खनन करवा लिया हैं। उनका एक ही लक्ष्य हैं पौधों की सिंचाई कर पेड़ बनाना और पुत्र की तरह देखभाल करना। इनकी इस पौधों के लिए त्याग, समर्पण और सेवा को देखकर ग्रामीण व अन्य लोग तारीफ करने से नहीं थकते। डूडा निवासी मनोहर सिंह बताते हैं कि बगीचे में आज आम, आंवला, कटहल सहित करीब 700 से अधिक पौधे व पेड़ हैं। अब तो आम और अमरूद के पेड़ ने फल देना शुरू कर दिया है। अपनी कडी मेहनत से उन्होंने बंजर और ककरीली जमीन पर भी पौधों से पेड बनाकर बंजर जमीन पर हरियाली बिखेर दी है। उन्होंने बताया कि परिवार और बगीचा उनके लिए दोनों समान है।

बाल्टी से पहुंचाया पानी

गांव के पास डेढ एकड़ से अधिक जमीन ककरीली और बंजर थी। जहां पौधरोपण तो हुआ है, लेकिन सिंचाई का कोई साधन नहीं था। पौधरोपण के बाद बाल्टी से सिंचाई की। अब ट्यूब बैल के पंप नहीं है। मैदान से कुछ दूर तेजराम साहू के मोटर पंप से बाल्टी पर पानी लाकर सिंचाई किया है। आज भी यहां मोटर पंप नहीं है। इसके बाद भी 15 सालों तक बाल्टी से पानी लेकर पौधों को पेड़ बना दिया।

वैज्ञानिक सलाह-किसानों को तीन वर्ष में बीज बदल देना चाहिए

टीकमगढ़। कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बीएस किरार, डॉ. आरके प्रजापति, डॉ. एसके सिंह, डॉ. यूएस धाकड़, डॉ. एसके जाटव, डॉ. आईडी सिंह, जयपाल छिगारहा एवं हंसनाथ खान द्वारा खरीफ मौसम की प्रमुख तिलहनी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई किस्म का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। किसानों को तीन वर्ष में बीज बदल देना चाहिए। वैज्ञानिकों द्वारा फसलों की नई किस्में अधिक उत्पादन, कीट व्याधियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता वाली के साथ-साथ उच्च पोषक तत्वों का भी समावेश किया जा रहा है। टीकमगढ़ जिले में प्रतिवर्ष मूंगफली का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। भारत सरकार का तिलहनी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा खाने वाली तेल फसलों पर विशेष परियोजना आदर्श तिलहन के नाम से शुरू की गई है। परियोजना के माध्यम से जिले की प्रमुख तिलहन फसलों में मूंगफली, तिल एवं सरसों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु किसानों को प्रशिक्षण, प्रदर्शन एवं भ्रमण के माध्यम से उन्नत तकनीक एवं नई किस्में

पहचाने का कार्य किया जाएगा। मूंगफली की नई किस्में जीआईजी-32, टीसीजीएच-1694 लीपाक्षी, सोयाबीन की नई किस्में में जेएस-20-116, जेएस-2094, जेएस-2098, जेएस-2069, जेएस-2034 राज सोया-18, आरवीएस-24, एवं तिल की किस्म जीटी-6 आदि किस्मों के लिए राष्ट्रीय बीज निगम निवाड़ी से संपर्क कर सकते हैं। किसान अधिक उत्पादन के लिए अनुसंशित बीज दर एवं फफूंद नाशक दवा से बीज उपचार कर ही बोवनी करें। उर्वरक का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर अनुसंशित मात्र का प्रयोग करें। तिलहनी फसलों में सल्फर एवं पोटाश युक्त उर्वरकों के उपयोग का विशेष ध्यान दें। खरीद फसलों में नींदा की मुख्य समस्या रहती है, इसलिए प्रारंभिक अवस्था में फसल को नींदा मुक्त रखने के लिए बोवनी के 15-25 दिन में पहली निराई-गुड़ाई और 35-40 दिन में दूसरी निराई-गुड़ाई करना चाहिए। खरीफ की फसलों को अधिक वर्षा के जल से बचाने के लिए खेत में जल निकास की नालियां अवश्य बनाना चाहिए।

विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया

हमें रख रखाव के साथ पशुओं के पोषण पर भी देना होगा ध्यान

रीवा। कृषि महाविद्यालय रीवा में विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि प्रो. एसके त्रिपाठी अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय रीवा, विशिष्ट अतिथि प्रो. आई खान पूर्व अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय गंजबसौदा थे। अतिथियों ने अपने संबोधन के दौरान दुध के महत्व और उसके उपयोगिता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के संयोजक डॉ. एके गिरी ने इस अवसर पर स्व डॉ. बरगीज कुरियन को याद करते हुए बताया कि स्वेत क्रांति के जनक थे, जिनके मार्गदर्शन में भारत आज विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। डॉ. गिरी ने कहा कि दुध की उत्पादकता और उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की अवश्यकता है, जो कि पशुओं के रख रखाव के साथ साथ उनके पोषण पर ध्यान देने से होगी। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रमुख डॉ. एके पांडेय ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन डा आर के तिवारी एवं धन्यवाद डा अखिलेश कुमार ने किया। इस अवसर पर महाविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केन्द्र के प्राध्यापक एवं अधिकारी कर्मचारी डॉ आर पी जोशी, डॉ यस म कुर्मवंशी, डॉ

बी के तिवारी, डॉ. जीडी शर्मा, डॉ. प्रदीप मिश्रा, डॉ. गुफरान, डॉ. सुधांशु पांडेय, ई सोनी, सुधीर सिंह, गुलसुप्रिया राय, भावना पारधी, छत्रसाल पांडेय, डीडी पटेल, गुलाब सिंह उपस्थित रहे।

एक ही बगीचे में 40 प्रकार के फलों के पेड़

रिटायरमेंट के बाद खेती से कमा रहे 8 लाख

नर्मदापुरम। जागत गांव हमार

जागत गांव हमार इस बार अपने पाठकों एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहा है, जो शौक के लिए लगाए फलों के बगीचे से लाखों रुपए कमा रहे हैं। पांच एकड़ में फैले इस बगीचे का नाम श्री राधा-कृष्ण की बगिया रखा है। नर्मदापुरम जिले के पथरौटा के रहने वाले 65 साल के रिटायर अधिकारी अरुण मेहतो ने अपने बगीचे में आम, चीकू, लीची, आंवला, करौंदा, अमरूद, जामुन, नाशपाती, एप्पल, बेर समेत 40 प्रकार के फलों के पेड़ लगाए हैं। इन पेड़ों के फल से हर साल करीब 6 से 7 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। श्री राधा-कृष्ण की बगिया औबेदुल्लागंज-बैतूल नेशनल हाईवे-46 किनारे स्थित है। हर साल बगीचा को नीलाम करते हैं।

जानते हैं किसान अरुण मेहतो से ही बगीचा शुरू करने की कहानी

पेड़-पौधों का बचपन से ही शौक है। मैं बचपन से ही इनकी सेवा करते आ रहा हूं। सर्विस में रहते हुए 2007 से बगीचे का शुरुआत किया था। उस समय मैं एसडीओ था, तो शनिवार और रविवार को आता था। पेड़ों को पानी देना, गुड़ाई करना, पेड़ों को देखरेख करना मैं खुद करता था। 2019 में बीएसएनएल के महाप्रबंधक के पद से रिटायर होने के बाद मैं अब ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। अभी मैं 4-5 घंटे बगीचे की ओर ध्यान दे रहा हूं। डेली आता हूं। पेड़ों में पानी देना, गुड़ाई करना मेरे डेली रुटिन में शामिल हो गया है। रिटायरमेंट के बाद बगीचा को थोड़ा और विस्तार किया है।

2012 में आम के पेड़ों में फल आने शुरू हो गए। इसके बाद मैंने धीरे-धीरे अलग-अलग फलों के पौधे भी लगाने लगा। मैं पहले दो-तीन पौधे ट्रायल के तौर पर लगाता हूं। अगर वे सक्सेस हो जाते हैं और फल आने लगते हैं तो उस फल के पौधे ओर लगाता हूं। लीची के भी मैंने पहले 2 पौधे लगाए थे। अब 110 लीची के पौधे हो गए हैं। बगीचे में 30 प्रकार की आम की वैरायटी है। इसमें हापुस, मियाजाकी, मल्लिका, आम्रपाली, दशहरी, लंगड़ा, बादाम, बॉम्बे ग्रीन, चौसा और देसी आम है। मैंने कुछ आम के पौधे हैदराबाद से मंगवाए थे और कुछ पौधे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने दिए थे। आम्रपाली आम दशहरी और नीलम का क्रॉस वैरायटी है। ये आम हर साल आता है।

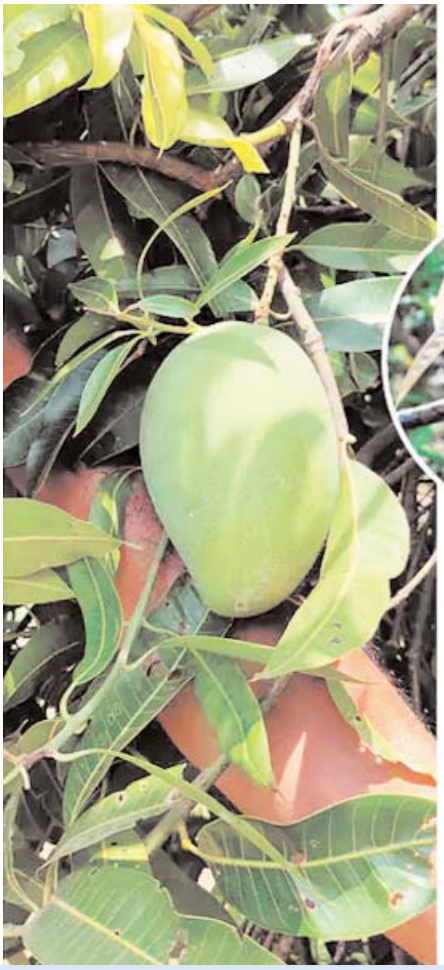

एक बार पौधा पेड़ बन जाए तो फिर चिंता नहीं रहती

इस बगीचे में करीब 600 से ज्यादा फलों के पेड़-पौधे हैं। जिसमें आम के 120, लीची के 110, चीकू के 32 पेड़ के अलावा आंवला, करौंदा, अमरूद, जामुन, नाशपाती, एप्पल, बेर, अनार, कटहल समेत 40 प्रकार के फलों के पेड़ हैं। दो साल पहले स्टार फ्रूट एप्पल के दो, नाशपाती के दो पौधे, वाटर एप्पल, अंजीर, काजू के दो-दो पौधे लगाए हैं। जो अब बड़े हो रहे हैं। अगले साल तक इनमें फल आना शुरू हो जाएंगे। यूएसए का फल एवोकाडो के भी दो पौधे लगाए हैं। महंगे आमों में मशहूर मियाजाकी के 3 पौधे भी लगाया है। इसमें से कुछ पौधे मैंने ऑनलाइन भी मंगवाए हैं। बगीचे से हर साल करीब 6 से 7 लाख रुपए का मुनाफा हो रहा है। पेड़ों के बीच-बीच में जो जगह बची है। उसमें पहले पौधे छोटे थे तो पपीता लगाता था। उससे भी अच्छी खासी इनकम होती है। उसके बाद इसमें मैंने टमाटर लगाया। इस साल मैंने सरसों लगाया था। जिसमें मुझे करीब एक से डेढ़ लाख की आमदनी हुई।

गोबर खाद से जमीन की उर्वरक क्षमता बनी रहती है

बगीचे में गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं। इससे जमीन की उर्वरक क्षमता बनी रहती है। सिर्फ बीमारियों से बचाव के लिए ही रासायनिक दवाओं का छिड़काव बगीचे में करते हैं। गोबर खाद मिट्टी की संरचना में सुधार करती, मिट्टी के लाभकारी जीवाणुओं और केंचुओं के लिए बेहद फायदेमंद होती है। गोबर की खाद में 50 फीसदी नाइट्रोजन, 20 प्रतिशत फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है। जो पौधों के पोषण के लिए जरूरी होता है। चीकू के पेड़ों में अभी तक किसी दवा की आवश्यकता नहीं पड़ी। आम और लीची में कभी-कभी दवा का छिड़काव करते हैं। दीमक न लगे इसके लिए चूना और नीला थोता पोता जाता है।

ऐसे लगा सकते हैं आम, लीची, चीकू का बगीचा

किसान अरुण मेहतो ने बताया कि आम, चीकू, लीची का बगीचा तैयार करने के लिए खेत में पहले 10 फीट की बराबर दूरी पर गड्ढे खोद लेते हैं। इन गड्ढों को खोदने के बाद इसमें कुछ गोबर खाद मिलाकर मिट्टी डालते हैं। कुछ दिनों तक इन गड्ढों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। 8 से 10 दिन बाद इनमें पौधे लगाते हैं। इन पौधों की कुछ दिनों तक लगातार देखभाल करनी होती है। उन्होंने बताया कि यदि पौधों पर कोई बीमारी आती है, तो उस पर दवाई का छिड़काव भी करना पड़ता है। जब पौधे 6 महीने से ज्यादा के हो जाते हैं, तो इतनी समस्या नहीं आती। एक बार पौधा पेड़ बन जाए तो फिर चिंता नहीं रहती है।

अगर पौधे छोटे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें

किसान अरुण मेहतो का कहना है कि छोटे-छोटे पेड़ में सावधानीपूर्वक ही खाद देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा खाद पड़ जाने से पेड़ सूख जाता हैं। खाद एवं उर्वरकों का इस्तेमाल सितंबर महीने के पहले हफ्ते तक कर लेना चाहिए। यदि किसी वजह से खाद एवं उर्वरकों का इस्तेमाल समय रहते नहीं कर पाए हों, तो 15 सितंबर के बाद इनका प्रयोग नहीं करें, क्योंकि इसके बाद बाग में जुताई गुड़ाई, खाद व उर्वरकों के प्रयोग से बाग में मंजर निकलने के स्थान पर नई-नई पत्तियां निकल आएगी। इसकी वजह से फायदा होने की बजाय नुकसान हो जाएगा।

कीटों से ऐसे बचाते हैं

आम के बाग में जनवरी से लेकर मार्च तक जमीन से गुजिया कीट निकलकर पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। इन कीटों की ज्यादा संख्या से नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये कीट पेड़ पर चढ़कर पत्तियों और बौर का रस चूसकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। प्रति बौर कीट की ज्यादा संख्या होने से फल भी नहीं बन पाते हैं। इन कीटों की वजह से पत्तियों और बौर में चिपचिपा पदार्थ बढ़ जाता है, जिससे फफूंद बढ़ने लगते हैं। अगर ये कीट पत्तियों और बौर पर दिखाई दें तो इनके प्रबंधन के लिए 20 लीटर पानी में पांच ग्राम छिड़काव करते है।

2 साल तक पौधों की करें नियमित सिंचाई

आम के पौधे लगाने के लिए सबसे सही समय बारिश का मौसम होता है। जुलाई से लेकर सितंबर तक आम के पौधे लगाए जाते हैं। पौधे लगाने के बाद दो साल तक नियमित सिंचाई की जरूरत होती है। छोटे पौधों को गर्मियों में 4 से 7 दिन के अंतर पर और सर्दी के मौसम में 10-12 दिन के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए। फल वाले पेड़ों की अक्टूबर से जनवरी तक सिंचाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अक्टूबर के बाद यदि भूमि में नमी अधिक रहेगी तो फल कम आते हैं। मिट्टी में कितनी नमी है, इसे टेंसियोमीटर नामक यंत्र से नापते हैं। यह मिट्टी की नमी का पता लगाने में मददगार होता है।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा-प्रदेश में वाटर स्पोर्ट को मिलेगा प्रोत्साहन

जल गंगा संवर्धन अभियान में 5.5 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रदेश में जल संरक्षण के लिए विशेष तौर पर जल गंगा संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दूसरे दिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल में छोटे तालाब पर स्थित जलक्रीड़ा केंद्र पहुंचे और श्रमदान करते हुए आमजन को इस अभियान में बढ़-चढ़कर सहभागिता करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर उन्होंने तालाब के तट पर साफ-सफाई करते हुए स्वच्छता में योगदान दिया। इस दौरान उनके साथ उनके साथ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विश्वास सारंग, राज्यमंत्री कृष्णा गौर, भोपाल के नवनिर्वाचित सांसद आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा, महापौर मालती राय समेत अनेक नेता व पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। जलक्रीड़ा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि भोपाल सबको अपने में समाहित करने वाली संस्कृति का शहर है। गत साठ-सत्तर वर्ष में देश के विभिन्न भागों से यहां आए लोगों ने भोपाल को राजधानी का स्वरूप दिया और विभिन्न भागों से आई धाराएं यहां समाहित हुईं। उन्होंने भोपाल में छोटे तालाब की साफ-सफाई के लिए नगर निगम भोपाल द्वारा जन-भागीदारी से चलाए जा रहे अभियान की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित किया जाएगा। भोपाल के साथ-साथ इंदौर और उज्जैन में भी वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। अगले ओलिंपिक में पदक लाना हमारा लक्ष्य होगा।

जल संरक्षण के साथ पौधारोपण को भी बढ़ावा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि 5 जून से प्रदेश में आरंभ जल गंगा संवर्धन अभियान में जल-स्रोतों के संरक्षण और साफ-सफाई के साथ-साथ इन स्थानों पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाए। प्रदेश में अभियान अवधि में 5 करोड़ 50 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य है। संपूर्ण प्रदेश में जन भागीदारी से पौधे लगाए जाएंगे। जल-गंगा संवर्धन अभियान, गंगा दशमी के बाद भी जारी रहेगा, सभी स्थानीय निकाय अपने-अपने स्तर पर अभियान संबंधी गतिविधियां संचालित करेंगे। हरियाली अमावस्या के बाद सघन रूप से पौधरोपण की गतिविधियां संचालित की जाएंगी।

मध्यप्रदेश देश की नदियों का केंद्र बिंदु

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नदी, पर्वत और पृथ्वी में जीवन माना गया है। मध्यप्रदेश देश की नदियों का केंद्र बिंदु है। यहां से सभी दिशाओं में बहने वाली नदियों की उत्पत्ति होती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेई के नदी जोड़ो अभियान की संकल्पना को मूर्तरूप देते हुए केन-बेतवा लिंक परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर राज्य सरकार को 45 हजार करोड़ तथा उत्तरप्रदेश सरकार को 45 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराये हैं। सीएम ने कहा कि इस परियोजना से शूरवीरों की धरती बुंदेलखंड को सिंचाई की सुविधा मिलेगी और वहां जीवन सरल होगा। इसी प्रकार प्रधानमंत्री मोदी ने पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना को भी स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रदेशवासी उनके आभारी हैं।

जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत पंचायत मंत्री ने किया पौधरोपण

जल स्त्रोतों के जल संरक्षण-पुनर्जीवन के लिए हम सब को होना होगा एकजुट

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुसार जल गंगा संवर्धन अभियान में प्रदेश में जल स्त्रोतों तथा नदी, तालाबों, कुओं, बावड़ियों तथा अन्य जल स्त्रोतो के जल संरक्षण एवं पुनर्जीवन के लिये 16 जून तक विशेष अभियान संचालित किया जाएगा। हम अपने पुरखों के अनुभव और उनके दूरदर्शी विचारों पर गौर करें। गंगा दशहरा के पहले किसान बंधु मेढ़ बंधान एवं खेती किसानी के लिए जो आवश्यक तैयारियां करना है वो पहले कर लेते हैं। क्योंकि उन्हें मालूम है कि बरसात आएगी, तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यह हमारे पुरखों-बुजुर्गों की सोच थी। हमें भी अपनी भावी पीढ़ी के बारे में सोचना होगा। यह बात पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने जल स्त्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए चलाए जा रहे जल-गंगा संवर्धन अभियान के दूसरे दिन ग्राम पंचायत बाबरिया में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही।

पौधों की जानकारी भी हो- मंत्री ने कहा कि जल स्त्रोतों के पास कौन से पौधे लगाए जाएं, जो जल के स्त्रोत को प्रवाहमान बनाए रख सकें इसके लिए हमें उन पौधों की जानकारी भी हो। ऐसी सूची बनाकर लोगों तक पहुंचाएं, जिससे लोगों को पता चल सके। बरसात के पानी का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है। यह भू-जल स्तर वृद्धि में सहायक सिद्ध होगा।

प्रकृति का दोहन खतरनाक

मंत्री ने सींगरी नदी के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि सींगरी नदी के भविष्य को देखें। पहले सींगरी नदी का स्वरूप कैसा था और आज सींगरी नदी की हालत क्या हैं। हम सींगरी को संरक्षित करके रखते तो आज वह बारहमासी होती। पांच नदियां करेली के पहले मिलती हैं, पर एक बूंद पानी भी नर्मदा नदी के भीतर नहीं जाता। इससे ज्यादा कोई दूसरा प्रमाण नहीं हो सकता। हम दिन-रात जिस तरीके से प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, यह हम सबके लिए खतरनाक है। यदि हम अच्छा काम करेंगे, तो उसका लाभ हमारे बच्चों को मिलेगा। हम क्या करना चाहते हैं यह हमें तय करना पड़ेगा।

सींगरी के कारण नरसिंहपुर हुआ समृद्ध

सींगरी के कारण नरसिंहपुर समृद्ध हुआ। सींगरी नदी से 12 से 13 पंचायत के लोग खेती सिंचाई तो करते हैं, लेकिन सींगरी को देना नहीं चाहते। उन्होंने यहां मौजूद किसानों से कहा कि हमें भू-जल स्तर को बनाए रखना होगा। पानी के बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। अधिक लालच भावी पीढ़ी का भविष्य नष्ट कर देगा। सींगरी नदी के स्त्रोत को बचाने के लिए कोशिश की गई थी। सींगरी नदी में पानी बहता रहे, इससे ज्यादा आनंद की अनुभूति और क्या होगी।

सरकार की तैयारी! दुग्ध उत्पादकों को अब मिलेगा पांच रुपए बोनस

दो लाख किसानों को मिलेगा लाभ

भोपाल। मध्यप्रदेश के दूध उत्पादकों के लिए एक खुशखबरी है। प्रदेश की मोहन सरकार कर्नाटक और राजस्थान की तर्ज पर दूध उत्पादकों को पांच रुपए प्रति लीटर बोनस देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार नई योजना लेकर आ रही है। जिसका नाम मुख्यमंत्री सहकारी दूध उत्पादक प्रोत्साहन योजना होगी। इसके लिए पुशपालन विभाग ने प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेजा है। दरअसल, मोहन सरकार की इस नवीन योजना के लिए 800 करोड़ की मांग की गई है। योजना को लेकर पहले भी मंथन किया जा चुका है। अब प्रमुख सचिव स्तर पर बैठक होगी और योजना को लागू करने को लेकर विचार किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से हजारों दुध उत्पादकों को लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि योजना के माध्यम से प्रदेश के दूध उत्पादकों को मप्र स्टेट को-ऑपरेरिट डेयरी फेडरेशन द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ उन्ही उत्पादकों को मिलेगा जो सांची ब्रांड को दूध उपलब्ध कराते है।

सांची दुग्ध सहकारी फेडरेशन को प्रदेश के करीब 2 लाख से अधिक किसान 19 हजार मीट्रिक टन दूध उपलब्ध कराते हैं। मोहन सरकार इन किसानों को कर्नाटक और राजस्थान सरकार की तर्ज पर प्रोत्साहन राशि देने की तैयारी में जुटी हैं। इन राज्यों में दूध उत्पादकों को पांच रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

वित्त विभाग की मंजूरी के बाद योजना की शुरुआत की जाएगी। प्रदेश के मुखिया मोहन यादव कई बार दुग्ध उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए जोर दे चुके हैं। सीएम सहकारिता आंदोलन को बढ़ाने के लिए किसानों को जोड़ने की बात कई बार कह चुके हैं।

लखन पटेल, पशुपालन एंव डेयरी राज्य मंत्री

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)